



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052025-262906
CG-DL-E-05052025-262906

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1973]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2025/वैशाख 15, 1947

No. 1973]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2025/VAISAKHA 15, 1947

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2025

का. आ. 2017(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (तीन सौ अस्सीवां संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
- भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में, “उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, उप-शीर्षक “क. उपभोक्ता मामले विभाग” के अधीन-
 - ‘अंतर्राज्यिक व्यापार: स्परिटयुक्त निर्मिति (अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (1955 का 39)’ से संबंधित प्रविष्टि 2 का लोप किया जाएगा;
 - प्रविष्टि 7 में, हिन्दी में संशोधन की आवश्यकता नहीं है;
 - प्रविष्टि 9 में, शब्दों, अंको और कोष्ठकों ‘बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60)’, के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक ‘विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1)’ रखे जाएंगे;

- (iv) प्रविष्टि 10 में, शब्दों, अंको और कोष्ठकों 'भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63)', के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक 'भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)' रखे जाएंगे;
- (v) प्रविष्टि 15 में, शब्दों, अंको और कोष्ठकों 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68)' के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35)' रखे जाएंगे।

द्रौपदी मुर्मु,

राष्ट्रपति

[फा.सं. 1/21/8/2024-मंत्रि.]

सतेन्द्र सिंह, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2025

S.O. 2017(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely: -

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Three Hundred and Eightieth) Amendment Rules, 2025.
(2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE, under the heading "MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (UPBHOKTA MAMLE, KHADYA AUR SARVAJANIK VITARAN MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS (UPBHOKTA MAMLE VIBHAG)"-
 - (i) entry 2 relating to 'Inter-State Trade: The Spirituous Preparation (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955 (39 of 1955)' shall be omitted;
 - (ii) in entry 7, for the word 'Meterology', the word 'Metrology' shall be substituted;
 - (iii) in entry 9, for the words, figures and brackets 'The Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976)', the words, figures and brackets 'The Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010)' shall be substituted;
 - (iv) in entry 10, for the words, figures and brackets 'The Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)', the words, figures and brackets 'The Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016)' shall be substituted;
 - (v) in entry 15, for the words, figures and brackets 'The Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)', the words, figures and brackets 'The Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019)' shall be substituted.

DROUPADI MURMU,

President

[F. No. 1/21/8/2024-Cab.]

SATENDRA SINGH, Addl. Secy.